बधाई दिल्ली। प्रदूषण के ख़िलाफ़ युद्ध में दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर की शुरुआत की। अमेरिकी तकनीक से बना ये स्मॉग टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करेगा। —— अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

15 सितम्बर तक ई फाइलिंग पोर्टल की समस्याएं दूर करे इंफोसिस।

—— निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

आईआईटी दिल्ली के शोधार्थियों ने विकसित किया प्रदूषणरोधी कपड़ा

यह कपड़ा हवा से हानिकारक वायु प्रदूषक कणों को सोखने में सक्षम

इसका उपयोग घरों, कार्यालयों, थिएटरों, हवाई जहाजों और अन्य परिवहन वाहनों जैसे बंद स्थानों में किया जा सकता है

नई दिल्ली (आईएएनएस)। आईआईटी दिल्ली की एक शोध टीम ने विशेष ने प्रदूषणरोधी सूती कपड़ा विकसित किया है। यह कपड़ा हवा से हानिकारक वायु प्रदूषक कणों को सोखने में सक्षम है। आईआईटी दिल्ली के कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग में स्मिता रिसर्च लैब में प्रोफेसर अश्विनी के अग्रवाल और प्रो. मंजीत जस्सल एवं भौतिकी विभाग में प्रोफेसर शाश्वत भट्टाचार्य के नेतृत्व में यह रिसर्च किया गया है।

इस संशोधित सूती कपड़े के बारे में प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल ने कहा, यह सूती कपड़ा तेजी से और आसान के साथ पर्यावरण के अनुकूल इनडोर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक बड़ी क्षमता है। इन कपड़ों का उपयोग गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए असबाब के रूप में किया जा सकता है। विशेष रूप से इनका उपयोग घरों, कार्यालयों, थिएटरों, हवाई जहाजों और अन्य परिवहन वाहनों जैसे बंद स्थानों में किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि यह जिओलाइट इमिडाजोलेट फ्रेमवर्क संशोधित कार्यात्मक कपड़े हैं, जो परिवेशी वायु से बेंजीन, एनिलिन और स्टाइरीन जैसे कार्बनिक वायु प्रदूषकों के उच्च स्तर को सोख लेते हैं। आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलरहरदीप सिंह के अनुसार सक्रिय कार्बन, जिओलाइट्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) जैसा झरझरा पदार्थ हवा से वीओसी को सोखने में सक्षम हैं। एमओएफ को ऐसे वस्त्र बनाने में किया सकता है जिनमें एंटीमाइक्रोबायल, बायोमेडिकल, पार्टिकुलेट मैटर फिल्टरिंग, ईंधन फिल्टरिंग, रसायनिक युद्ध सुरक्षा और यूवी विकिरण अवशोषित गुण होते हैं। जिओलाइट इमिडाजोलेट फ्रेमवर्क विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त हैं। तेजी से पानी आधारित कपड़ा परिष्करण दृष्टिकोण का उपयोग करके कार्बोक्सिमिडाइलेटेड इस सूती कपड़े पर नैनोक्रिस्टल के इन-सीटू विकास के रूप में जानी जाने वाली तकनीक का उपयोग करते हुए आईआईटी दिल्ली के शोधकर्तावों ने यह कम लागत वाला सूती कपड़ा सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो साधारण सूती कपड़ों की तुलना में 400-600 फीसद अधिक वीओसी सोखने में सक्षम है। इसके अलावा, ये कपड़े मजबूत हैं और धोने की कठोर परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। इनका बार-बार उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में आए विप सदस्य

नई दिल्ली, (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय मंगलवार को अपनी विद्वत परिषद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके एजेंडे को पास करने के लिए लेकर आ रही। इसको स्वीकृति प्रदान करने वाले ज्यादातर सदस्यों ने इसका विरोध करने का फैसला लिया है।

उनका कहना है कि इस नीति का वे विरोध करेंगे। विद्वत परिषद के सदस्य डा. सुधांशु कुमार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सारे बड़े फैसले हैं। हड़बड़ी में इसे लागू करना न केवल गलत है बल्कि नैतिक रूप से भी सही नही है। इन नियमों के लागू होने से लगभग 40% तक वकेलोड पर असर पड़ेगा। वर्षों से एडहॉक पर पढ़ा रहे शिक्षको की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हम मीटिंग में हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे।

अफगानिस्तान में गहराते संकट के बीच सोमवार को यूएनएचसीआर कार्यालय के सामने विरोध-प्रदर्शन करतीं अफगानी महिला शरणार्थी। इस दौरान बच्चे भी मौजूद रहे। सभी फोटो : प्रेट्र/ लेखराज

यूएनएचसीआर कार्यालय के सामने अफगान शरणार्थियों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली (वार्ता)। अफगानिस्तान के नागरिकों ने शरणार्थी का दर्जा देने के साथ ही रोजगार एवं आवास की सुविधा देने की मांग को लेकर सोमवार को यहां संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। राजधानी के वसंत विहार कार्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों के अलावा मासूम बच्चे शामिल हुए। हाथों में अपने देश का झंडा लिये आंदोलनकारी 'वी वांट फ्यूचर' के साथ भारत या किसी अन्य देश में शरण देने के साथ ही रोजगार, आवास एवं सुरक्षा की मांग कर थे। कोरोना के महेनजर चेहरे पर मास्क लगाने के अलावा अन्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन लोगों ने प्रदर्शन किया।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से दूसरे देशों में प्रवास करने के लिए 'समर्थन पत्र' जारी करने की मांग की

उनका कहना था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मामले में जल्दीबाजी की गई, जिससे वहां के हालात बेकाबू हो गये। इस मामले में वहां के हालात का सही आंकलन नहीं किया गया। इसका खमियाजा उनके मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है जिसका उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर यूएनएचआरसी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वहां के नागरिकों को समुचित सुरक्षा दी जा रही है।

REGISTERED EDUCATIONAL SOCIETY
having 80G & 12A seeking donation, interested persons/ establishments may contact:
9811734420
email :
gbsociety@gmail.com

पहला स्मॉग टावर बताने पर भाजपा ने जताई आपत्ति

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

राजधानी के लुटियन इलाके में सोमवार से शुरू हुए स्मॉग टावर को पहला टावर बताने पर प्रदेश भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अपनी संस्था की तरफ से दिल्ली को 3 स्मॉग टावर वर्ष 2020 में ही दे चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि के जरीवाल सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर नही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार कनॉट प्लेस में शुरू हुए स्मॉग टावर को पहला टावर बता रही है, जबकि पहला स्मॉग टावर भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पिछले साल जनवरी में लाजपत नगर में लगवाया था। इसके बाद भाजपा सांसद ने गांधी नगर और कृष्णानगर में स्मॉग टावर लगवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब सात साल से दिल्ली के लोग प्रदूषण से जूझ रहे है, लेकिन सरकार इससे राहत के लिए कोई गंभीर प्रयास करती दिख नही रही।

जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड
JUBILANT FOODWORKS
सीआईएन: L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट 1ए, सेक्टर 16ए, नोएडा-201 301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालय: 5वीं मंजिल, टॉवर डी, लोजिक्स टैक्नो पार्क, सेक्टर 127, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश
फोन: +91-120-4090500, **फैक्स:** +91-120-4090599
वेबसाइट: www.jubilantfoodworks.com, **ईमेल:** investor@jubl.com

26वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबंन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी विभिन्न सर्कुलर्स के अनुपालन में, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), शुक्रवार, 17 सितम्बर, 2021 को पूर्वा. 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जा चुकी है, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट (डीपी) के पास पंजीकृत है। सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना ई-मेल करने का कार्य 23 अगस्त, 2021 को पूर्ण किया जा चुका है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यगण, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डीपी के पास पहले से पंजीकृत है, वे रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए एजीएम में उपलब्ध कराए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं है, वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं इत्यादि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत अथवा अद्यतन कराने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ई-मेल आईडी का सफल पंजीकरण होने पर, ई-वोटिंग के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा :

(i) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में धारण किए हुए हैं, वे लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी का आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपनी ई-मेल आईडी अथवा रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं। तथापि, ई-मेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

(ii) सदस्यगण, जो कम्पनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं, वे लिंक : https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दी गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करके कम्पनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. के पास अपना विवरण पंजीकृत करवा सकते हैं।

(iii) विकल्पतः शेयरधारक/सदस्यगण ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए, एजीएम की सूचना में वर्णित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए एक अनुरोध evoting@nsdl.in पर भेज सकते हैं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, समय समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबंन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीबंन विनियमावली') के विनियम 44 के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम में निष्पादन हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) तथा ई-वोटिंग की सुविधा (एजीएम में) उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों को वीसी/ओएवीएम बुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके द्वारा प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है। उक्त सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 26वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
2. सदस्यों के वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 अर्थात कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है, केवल वही एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का हकदार होगा।
3. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजी जा चुकी होने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 को शेयरों का धारक है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा investor@jubilant.com पर अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी के उल्लेखयुक्त ई-मेल भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
4. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 14 सितम्बर, 2021 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी तथा बुहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021 (अपं. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
5. इस अवधि के दौरान, भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं।
6. सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे वे सदस्य, जिनके द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में वोट डालने के हकदार होंगे।
7. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते/भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
8. रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एवं विधि तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए जा रहे हैं।
9. किसी संदेह की स्थिति में, आप सदस्यगण, www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोलफ्री नंबर : 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 को evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण करेंगी।
10. परिणामों की घोषणा एजीएम के समापन के दो कार्यदिवस के भीतर की जाएगी तथा उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।

कृते **जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड**
हस्ता/-
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 23 अगस्त, 2021
स्थान: नोएडा (उत्तर प्रदेश)

डीयू : दिल्ली सरकार के 6 कॉलेजों को मिला फंड

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

काफी विरोध के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध व दिल्ली सरकार द्वारा 100 फीसद वित्त पोषित 12 कॉलेजों में से सिर्फ 6 कॉलेजों को फंड जारी किया गया है। अब शिक्षकों व कर्मियों को ढाई से तीन महीने का वेतन मिल सकेगा।

बाकी 6 कॉलेजों के फंड के लिए सरकार को लिखेंगे पत्र : प्रो पाणी

डीयू के डीन कॉलेजेस प्रो. बलराम पाणी ने कहा कि जिन कॉलेजों को फंड नही जारी हुआ है, उसके लिए हम सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं। प्रो. पाणी ने बताया कि उनके कॉलेज को करीब सवा पांच करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। इससे कॉलेज स्टाफ की ढाई से तीन महीने तक की सैलरी दी जा सकेगी। इसी प्रकार शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज को सवा पांच करोड़ रुपए का फंड दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार कॉलेजों को अलग-अलग व्यक्तिगत तरीके से फंड जारी किया गया है, जबकि पहले एक साथ कॉलेजों को फंड दिया जाता था।

दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्राचार्य प्रो. हेमचंद जैन ने बताया कि हमें भी अभी तक फंड जारी नही किया गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे कॉलेज को कल तक फंड मिल सकता है। हमारे कॉलेज को साढ़े सात करोड़ रुपए के फंड की जरूरत है। इसके अलावा, अदिति कॉलेज, केशव कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज और महाराजा अग्रसेन कॉलेज को अभी फंड जारी नही हुआ है। प्रो. जैन ने बताया कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज को करीब साढ़े सात करोड़ रुपए, शहीद राजगुरु कॉलेज को साढ़े पांच करोड़ रुपए कॉलेज, महर्षि बाल्मीकि कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भगिनी निवेदिता कॉलेज को भी फंड जारी किया जा चुका है। प्रो. पाणी ने कहा कि छह कॉलेजों में करीब 1 हजार से ज्यादा का स्टाफ है, जिनको अभी वेतन मिलना है। हमारी सरकार से मांग है कि बाकी कॉलेजों को भी जल्द फंड जारी किया जाए।

उत्तर रेलवे ने समयबद्धता को 93% तक हासिल बनाए रखा रिकार्ड

उत्तर रेलवे की बैठक में गतिशीलता में वृद्धि, संरक्षा और ढांचागत कार्यों की हुई समीक्षा

'भारतीय रेलवे की रेलगाड़ियों में बायो-वैक्यूम हाईब्रिड शौचालय' पर एक पुस्तिका का हुआ विमोचन

नई दिल्ली (एसएनबी)। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर रेलवे के विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में रेलपथों पर संरक्षा, समयपालनबद्धता, गतिशीलता में वृद्धि संबंधी कार्यों, माल लदान और आय में वृद्धि इत्यादि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। उत्तर रेलवे ने समयपालनबद्धता को 93% तक हासिल करके इसके बेहतर रिकॉर्ड को बनाए रखा है।

गंगल ने उत्तर रेलवे के यांत्रिक विभाग द्वारा तैयार 'भारतीय रेलवे की रेलगाड़ियों में बायो-वैक्यूम हाईब्रिड शौचालय' पर प्रकाशित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि संरक्षा उत्तर रेलवे की प्राथमिकता है। उन्होंने रेलपथों, वैल्डों के अनुरक्षण मानकों और रेलपथों के निकट पड़े स्क्रैप को हटाने के लिए जोन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मण्डलों को गतिशीलता बढ़ाने संबंधी कार्यों में तेजी लाने और कार्यों की प्रगति की जांच करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेल पटरियों की दरारों और रेल वैल्डों की गहन निगरानी की जानी चाहिए और कोई त्रुटि नही छूटनी चाहिए। उन्होंने रेल परिचालन के दौरान आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों को समयपालनबद्धता को 95% पर बनाए रखने और संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए माल लदान की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

कोरोना के दौरान डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ा

एसटीएफ अतिक्रमण रोकने में रही असफल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों की मानें तो बीते करीब डेढ़ साल यानी कोरोना काल में प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ा है। इस दौरान स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने भी अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई नही की है। खासबात यह है अधिकतर अतिक्रमण के मामले उस जमीन पर सामने आ रहे है, जो गावों एवं यमुना नदी के आसपास है।

राजधानी में डीडीए को अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि डीडीए ने अपनी जमीन को बचाने के लिए 2015 में एक बड़ा सर्वे कराया था। सर्वे के बाद डीडीए ने दावा किया था कि बड़ी तादात में ऐसी जमीन चिह्नित की गई है, जिस जमीन पर अतिक्रमण है या फिर उस जमीन अतिक्रमण करने वालों की नजर है। डीडीए ने एक पोर्टल भी बनाया था और लोगों से आग्रह किया था कि लोग इस तरह के मामलों की जानकारी दे सकते है। पोर्टल पर फोटो अपलोड की भी व्यवस्था की गयी थी।

सूत्रों की मानें तो डीडीए को पोर्टल से काफी जानकारी मिली थी। एक अधिकारी का कहना है कि डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है। सूत्र यह भी बताते है कि कोरोना काल में अतिक्रमण तेजी से बढ़ा है। इस दौरान नोएडा की सीमा से लगी डीडीए की जमीन पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है। कमोबेश यही स्थिति यमुना नदी के किनारे वसे गावों की है। ओखला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसी तरह मदनपुर खादर, जैतपुर के आसपास भी डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। यह हाल तब जब डीडीए की अपनी एसटीएफ है। एसटीएफ गठित करने का मूल्य उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से बचाना है।

माता सावित्रीबाई फुले व चौधरी ब्रह्मप्रकाश के नाम पर कॉलेज खोलने की मांग

नई दिल्ली, (एसएनबी)। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन (डीटीए) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति व काउंसिल के चेयरमैन प्रो. पीसी. जोशी से माता सावित्रीबाई फुले के नाम से दिल्ली देहात के फतेहपुरबेरी में और दिल्ली देहात के नजफगढ़ (रोशनपुरा) में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री जननायक चौधरी ब्रह्मप्रकाश के नाम पर कॉलेज खोलने की मांग की है।

डीटीए के अध्यक्ष डॉ. हंसराज ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली सरकार में वर्तमान में एक भी पिछड़ी जाति की किसी भी महिला के नाम पर कोई कॉलेज या शिक्षण संस्थान नही है। माता सावित्रीबाई फुले के नाम से यदि कॉलेज खुलता है तो पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता थे जिनका आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे केवल दिल्ली देहात के ही नही बल्कि दलित, पिछड़ी जाति की आवाज थे उनके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक तरक्की की। उनके नाम पर सह शिक्षा महाविद्यालय खोलने से देहात के छात्र-छात्राओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा।

आज रद्द रहेंगी 27 ट्रेनें 11 के मार्ग में बदलाव

पंजाब में रेल पटरी नही हुई खाली, बढ़ी यात्रियों की परेशानी

नई दिल्ली (एसएनबी)। गन्ने का समर्थन मूल्य को लेकर पंजाब सरकार के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रहने से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की समस्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बीते शुक्रवार से पंजाब व जम्मू जाने वाली अधिकांश ट्रेनें रद्द है तो कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव कर चलाया जा रहा है। सोमवार को 48 ट्रेनें रद्द रही तो मंगलवार को भी 27 ट्रेनों को रद्द किये जाने की घोषणा कर गई है। 11 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने और 11 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त करने का फैसला किया गया है।

किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले शुक्रवार से पंजाब में जालंधर व फगवाड़ा के बीच रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे है जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई है। मंगलवार को रद्द रहने वाली प्रमुख ट्रेनें - नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलने वाली दोनों शताब्दी, अमृतसर-हरिद्वार जनशताब्दी, जम्मूतवी-सरयव रोहिल्ला एक्सप्रेस, शान-ए-पंजाब, पुरानी दिल्ली-पटानकोट एक्सप्रेस, नई दिल्ली-अमृतसर एक्सप्रेस।

डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर बैठक

नई दिल्ली (एसएनबी)। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने सोमवार को डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम के संबंध में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अतिरिक्त आयुक्त (स्वास्थ्य), सुनील भाटू, निगम स्वास्थ्य अधिकारी अशोक रावत व निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने निगम अफसरों को सभी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके।

पुराने इनकम टैक्स पोर्टल को बंद करने से पहले नए को परख लेती सरकार : सीटीआई

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

नए इनकम टैक्स पोर्टल को परखे बगैर पुराने पोर्टल को बंद करने से हुई गड़बड़ी

पोर्टल को लेकर जल्द समाधान निकाले केंद्र सरकार

लाखों कारोबारियों और एक्सपटर्स को हो रही परेशानी

लगातार दो दिनों से इनकम टैक्स पोर्टल के काम नहीं करने पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के संगठन सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि नए पोर्टल को अच्छी तरह परखने के बाद ही पुराने पोर्टल को बंद किया जाए।

नए से खुश नहीं, पर पुराना पोर्टल चालू नहीं होगा : पुराने पोर्टल से कोई समस्या नहीं थी। सभी यूटिलिटी सही से काम कर रही थीं। इसलिए कई स्टेक होल्डर्स की यह राय थी कि पुराने पोर्टल को ही फिर से चालू कर दिया जाए। इस सुझाव को फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते नकार दिया था। उनका तर्क था कि इस वक्त पुराने पोर्टल को फिर से लागू करने से समस्याएं बढ़ेगीं और नई उलझनें पैदा होंगी। दो दिन से नया पोर्टल पूरी से बंद है। समस्या की गंभीरता के देखते हुए इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारिख को सोमवार को वित्त मंत्री के सामने उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था।

इस मीटिंग के नतीजे का सभी स्टेक होल्डर्स को बेसब्री से इंतजार है। इन नेताओं ने कहा है कि इस मामले में केन्द्र जल्दबाजी न दिखाए। गोयल ने बताया कि क्रीब तीन महीने पहले 31 मई को सालों से काम कर रहा इनकम टैक्स का पोर्टल बंद कर दिया गया था। निर्धारित आदेशानुसार जून के पहले हफ्ते में इनकम टैक्स की ऑनलाइन सर्विसेज और यूटिलिटी पूरी तरह से बंद रहीं।

तय वक्त यानि कि 7 जून को पुराने की जगह इन्फोसिस द्वारा तैयार किया गया इनकम टैक्स का नया पोर्टल चालू कर दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अगले दिन टैक्सपेयर्स को बधाई दी और नए पोर्टल को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए इसे मील का पत्थर बताया।

उन्होंने कहा कि टैक्सपेयर्स के लिए नए पोर्टल पर काम एक सुखद अनुभव होगा। पुराने पोर्टल से कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं पड़ी। पर ऐसी उम्मीद थी कि नए पोर्टल पर ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। नए पोर्टल के लिए 4,242 करोड़ इन्फ्रोसिस को मिलेंगे। पुराना पोर्टल जो 31 मई को बंद कर दिया गया, वह टाटा कन्सेल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के जिम्मे था। सीटीआई ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि नए पोर्टल को अच्छी तरह परखने के बाद ही पुराने पोर्टल को बंद किया जाए लेकिन इसको लेकर केन्द्र ने जल्दबाजी दिखाई।

कार्यालय नगर पालिका परिषद हापुड़,(जनपद-हापुड़)
पत्रांक : 182/ 23/